2024

1. निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन-से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के 'नागरिकों' को अनुदत्त हैं?

(1) अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30
(2) अनुच्छेद 14, 20, 23 और 30
(3) अनुच्छेद 15, 21, 25 और 28
(4) अनुच्छेद 20, 21, 25 और 30
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 15,16, 19 और 30) केवल नागरिकों (Citizens) को ही प्रदान किए गए हैं, जबकि अन्य मौलिक अधिकार (जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 और 28) सभी व्यक्तियों (Persons) को दिए जाते हैं।
- **अनुच्छेद-15:** किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद-16:** समान अवसर और रोजगार में कोई भेदभाव न हो।
- **अनुच्छेद-19:** अभिव्यक्ति, आंदोलन, सभा, संघ बनाने के अधिकार।
- **अनुच्छेद-30:** अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार।

2. किस वर्ष भारत के संविधान में यह अन्तःस्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा?

(1) 1979
(2) 1978
(3) 1976
(4) 1975
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- भारत के संविधान में यह प्रावधान कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा, वर्ष 1976 में अन्तःस्थापित किया गया था।
- निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व - DPSP) में अनुच्छेद-39A के रूप में जोड़ा गया था। यह प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय मिले और विशेष रूप से, आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे।

3. सूची-A का सूची-B से मिलान कीजिये और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिये :

सूची-A वाद		सूची-B संशोधन को चुनौती	
A.	इंदिरा गाँधी बनाम राज नारायण	i.	42वाँ संशोधन
B.	मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ	ii.	52वाँ संशोधन
C.	किहोतो हॉलोहान बनाम जशीलू	iii.	39वाँ संशोधन
D.	पी. संबामूर्थि बनाम आंध्रप्रदेश राज्य	iv.	32वाँ संशोधन

कूट :

(1) A-iii B-i C-ii D-iv
(2) A-i B-iii C-iv D-ii
(3) A-ii B-iii C-i D-iv
(4) A-iv B-ii C-iii D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- इंदिरा गाँधी बनाम राज नारायण मामले में 39वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। इस वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखता था। यह बुनियादी संरचना सिद्धांत के तहत् एक प्रमुख निर्णय था।
- मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ में 42वें संविधान संशोधन की वैधता पर विवाद हुआ था। इस वाद में, न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया। इसने यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्त्वों के बीच संतुलन संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है।
- किहोतो हॉलोहान बनाम जशीलू वाद 52वें संशोधन (1985) से संबंधित है, जिसने दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) को 10वीं अनुसूची में जोड़ा था। न्यायालय ने इसमें कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा।
- पी. संबामूर्थि बनाम आंध्रप्रदेश राज्य मामले में 32वें संशोधन की वैधता पर विचार हुआ था। यह वाद 32वें संशोधन के तहत आंध्रप्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित है। न्यायालय ने इस संशोधन के तहत् किए गए कुछ प्रावधानों की व्याख्या की।

4. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(1) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक सौ के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आये।
(2) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें (ए) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और (बी) राज्यों की विधान सभाओं और विधान सभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
(3) निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती है।
(4) चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-
- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- MLA के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या/राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या)×(1/1000)।

5. लोक सभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिये :
(i) लोक सभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
(ii) जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाणपत्र दिया जाता है।
(iii) जब अध्यक्ष को हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाहियों में भाग लेंगे।
(iv) मतों की समानता के अलावा, अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते।
कूट :
(1) केवल (i), (ii) और (iii)
(2) केवल (i) और (iii)
(3) केवल (i) और (ii)
(4) केवल (i), (ii) और (iv)
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-
- **अनुच्छेद 118(4) के तहत,** संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करते हैं।
- **अनुच्छेद 110(3) के तहत,** यह निर्णय करने की शक्ति कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष के पास होती है, और उनका निर्णय अंतिम होता है। यह प्रमाणपत्र राज्य सभा को भेजते समय संलग्न होता है।
- **अनुच्छेद 96(1) के अनुसार,** जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें सदन में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है। उन्हें मत देने का अधिकार भी होता है, लेकिन केवल पहली बार में (समानता की स्थिति को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 100(1) के अनुसार,** अध्यक्ष सदन में केवल टाई या मतों की समानता की स्थिति में ही अपना निर्णायक मत (Casting Vote) देते हैं। सामान्य मतदान में वे भाग नहीं लेते हैं।

6. भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानें।
(1) राष्ट्रपति मुख्य चुनावः आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल पाँच वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
(2) भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी।
(3) बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहु-सदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है।
(4) संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात् निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-
- संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, नियुक्ति अब एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता, संघ कैबिनेट मंत्री (जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है)।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है।
- अनुच्छेद - 103 (संसद सदस्यों के लिए) और अनुच्छेद - 192 (राज्य विधानमंडल सदस्यों के लिए) के तहत, राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा सदस्य की निर्योग्यता पर निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग से राय लेना अनिवार्य है। यह आयोग का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है।
- भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
- बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहु-सदस्यीय आयोग की अवधारणा 1993 से स्थायी रूप से लागू है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

7. निम्नलिखित में से वह कौन-सा विषय है जिस पर 31 दिसम्बर, 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा?

(1) जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा।
(2) संविधान के अध्याय I भाग XII के तहत् संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के निवल आगमों का वितरण।
(3) वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करते हैं।
(4) पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- 31 दिसम्बर, 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 16वें वित्त आयोग अपनी सिफारिश निम्नलिखित विषयों पर करेगा:
- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत् संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगमों का वितरण।
- राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय।
- लेकिन, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा इस अधिसूचना में शामिल नहीं है।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिह्नित कीजिए:
(a) 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोक सभा स्थानों पर विजय प्राप्त की।
(b) 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोक सभा स्थानों पर विजय प्राप्त की।
(c) 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोक सभा स्थानों पर विजय प्राप्त की।
कूट :

(1) केवल (a) और (c) सही हैं।
(2) केवल (a) सही है।
(3) केवल (a) और (b) सही हैं।॥
(4) केवल (b) और (c) सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

2004 लोक सभा चुनाव परिणाम

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): 145 सीटें
- भारतीय जनता पार्टी (BJP): 138 सीटें
- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM): 43 सीटें
- इन चुनावों के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार बनी थी।

9. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर हुयी थी?

(1) बक्शी टेकचंद समिति (2) संथानम समिति
(3) केलकर समिति (4) स्वर्ण सिंह समिति
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

CVC और संथानम समिति

- **समिति का गठन:** 1962 में, भारत सरकार ने के. संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति (Committee on Prevention of Corruption) का गठन किया था।
- **सिफ़ारिश:** समिति ने 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और केंद्र सरकार के अधीन भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक कदाचार पर निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफ़ारिश की।
- **स्थापना:** इस सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना एक कार्यकारी प्रस्ताव (Executive Resolution) द्वारा की गई थी। इसे 2003 में CVC अधिनियम के माध्यम से सांविधिक दर्जा (Statutory Status) दिया गया।

2023

10. भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिये-
(i) संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ।
(ii) इस अंतिम अधिवेशन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद हेतु विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए।

(1) न तो (i) न ही (ii) सही है।
(2) (i) और (ii) दोनों सही हैं।
(3) केवल (ii) सही है।
(4) केवल (i) सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

- कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस नवगठित संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई जबकि इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में संविधान सभा के द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था।
- संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे।

11. भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन–सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गयी थी?

(1) छठी (2) दसवीं
(3) नवीं (4) सातवीं

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- वर्ष 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नौवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची शामिल होती है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती।

12. मेनका गाँधी वाद, 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद-21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।

(1) यह भार याचिकाकर्ता पर है, कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वह स्वेच्छाचारी है।
(2) 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान 'उचित प्रक्रिया' के मोटे तौर पर समर्थन है।
(3) अनुछेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं हैं।
(4) 'जीवन का अधिकार' मे गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है"। वर्ष 1978 में, मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-21 के संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिये। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है तथा मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल है।

13. राज्य सभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।

(1) डॉ. एस. राधाकृष्णन राज्य सभा के एकमात्र सभापति हैं, जो लगातार दो कार्यकाल इस पद पर रहे।
(2) प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्य सभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था।
(3) वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्य सभा में निर्वाचित होते हैं।
(4) तीन अवसरों पर राज्य सभा और लोक सभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1952 से 1962 तक लगातार दो कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इस प्रकार वह ऐसे पहले व्यक्ति थे, जो लगातार दो कार्यकाल तक राज्यसभा के सभापति रहे।
- मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में लगातार दो कार्यकाल 2007 से 2017 तक कार्य किया था ।

14. अविश्वास प्रस्ताव के संबंध मे निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(1) 15 अगस्त, 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए।
(2) लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया।
(3) जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है।
(4) अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में रखा जा सकता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[*]**

व्याख्या:-

- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

15. निम्नलिखित सूची-I (निदेशक सिद्धांत) को सूची-II (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I	सूची-II
A. समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता	I. अनुच्छेद 48
B. पर्यावरण की सुरक्षा	II. अनुच्छेद 39
C. काम करने का अधिकार	III. अनुच्छेद 41
D. स्मारकों का संरक्षण	IV. अनुच्छेद 49

सही विकल्प चुनें :

(1) A-I B-III C-IV D-II
(2) A-II B-I C-III D-IV
(3) A-III B-I C-IV D-II
(4) A-II B-III C-I D-IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता	अनुच्छेद 39 A
पर्यावरण की सुरक्षा	अनुच्छेद 48 A
काम करने का अधिकार	अनुच्छेद 41
स्मारकों का संरक्षण	अनुच्छेद 49

16. सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से सम्बन्धित नहीं है?

(1) 25 (2) 19
(3) 18 (4) 12
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-12 में केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन तथा धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तें तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-3 में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है।

17. निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर-राज्य परिषद के स्थान पर अंतर-सरकारी परिषद् स्थापित करने की अनुशंसा की थी?

(1) राजमन्नार आयोग
(2) पूंछी आयोग
(3) प्रशासनिक सुधार आयोग, 1969
(4) सरकारिया आयोग
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- 1983 में भारत सरकार द्वारा आर.एस सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद् की स्थापना की वकालत की, जिसे 'अंतर सरकारी परिषद्' का नाम दिया गया था।
- सरकारिया आयोग के गठन एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था।

18. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।
(i) राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई 'कांग्रेस प्रणाली' का वर्ष 1989 के लोकसभा चुनावों में अंत हो गया।
(ii) वर्ष 1989 के लोक सभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी।

(1) न तो (i) न (ii) सही है।
(2) (i) व (ii) दोनों सही हैं।
(3) केवल (i) सही है।
(4) केवल (ii) सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

- 1960 के दशक में एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार और कार्यकर्ता रजनी कोठारी द्वारा सर्वप्रथम "कांग्रेस प्रणाली" शब्द दिया गया था।
- वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस को 197 सीट हासिल हुई और जनता दल 143 सीटों के साथ दूसरे नंबर रही तथा श्री वी.पी सिंह बीजेपी और सीपीआई (M) की मदद से प्रधानमंत्री बने।

19. निम्नलिखित सूची-P (CAG) को सूची-R (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिये।

A. CAG की नियुक्ति	**I. अनुच्छेद-148**
B. CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ	**II. अनुच्छेद-151**
C. संघ के खातों का प्रपत्र	**III. अनुच्छेद-149**
D. ऑडिट रिपोर्ट	**IV. अनुच्छेद-150**

(1) A-I B-III C-IV D-II
(2) A-II B-I C-III D-IV
(3) A-III B-I C-IV D-II
(4) A-II B-III C-I D-IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- अनुच्छेद-148- यह CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 149 – यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 150 - संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा।
- अनुच्छेद 151 – इसके अंतर्गत संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।

20. संविधान के अनुच्छेद-217 [1] के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा?

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल ।
(2) राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति।
(3) संघ के कानून एवं न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल।
(4) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

- संविधान का अनुच्छेद-217[1] के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी जबकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

21. अगस्त, 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे?
(I) सर तेज बहादुर सप्रू
(II) जस्टिस फजल अली
(III) के.एम. पणिक्कर
(IV) हृदयनाथ कुंजरु
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये-

(1) केवल (II) और (III)
(2) केवल (II) और (IV)
(3) केवल (II), (III) और (IV)
(4) (I), (II), (III), और (IV)
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- 22 दिसम्बर, 1953 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सम्पूर्ण राष्ट्र में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाने की सिफारिश की।
- 29 दिसम्बर, 1953 को जस्टिस सैय्यद फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
- इस आयोग में हृदयनाथ कुंजरू और कवलम माधव पणिक्कर को सदस्य नियुक्त किया।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 सितम्बर, 1955 को अपनी अन्तिम सिफारिशें की।
- आयोग की सिफारिश पर 7वाँ संविधान संशोधन, 1956 (1 नवम्बर, 1956) लागू किया।
- इस संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणी A,B व C को समाप्त कर दिया।

2021

22. भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है–
(1) बी.पी. सिन्हा, पी.बी. गजेन्द्रगडकर, एस. आर. दास
(2) के. जी. बालकृष्णन, एस. एच. कापड़िया, एच. एल. दत्तु
(3) रंजन गोगोई, एन. वी. रमण, दीपक मिश्रा
(4) एच. एल. दत्तु टी. एस. ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर **[4]**

व्याख्या:-
- एच.एल दत्तू – सुप्रीम कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश
- टी.एस. ठाकुर – सुप्रीम कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश
- जगदीश सिंह खेहर – सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश

23. कथन (A): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है।
कारण (R): उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।
(1) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(4) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। **[2]**

व्याख्या:-
- कथन A और कारण (R) दोनों सत्य हैं एवं (R) (A) की सही व्याख्या है।
- भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद-148 के तहत स्थापित किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इसकी औचित्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ व्यय की वैद्यता सुनिश्चित करनी होती है। वह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

24. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए –

सूची-I संविधान सभा समिति		सूची-II अध्यक्ष	
A.	मूल अधिकार	(i)	बी. आर. अम्बेडकर
B.	कार्य संचालन	(ii)	जवाहरलाल नेहरू
C.	संघ शक्ति	(iii)	के. एम. मुंशी
D.	प्रारूप	(iv)	सरदार पटेल

कूट -

	A	B	C	D
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

[*]

व्याख्या:-
- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा?
(1) लोकसभाध्यक्ष (2) निर्वाचन आयोग
(3) उच्चतम न्यायालय (4) महान्यायवादी **[2]**

व्याख्या:-
- सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे।

26. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था?
(1) 98वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(2) 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(3) 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
(4) 100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम **[3]**

व्याख्या:-
- 2014 के 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) नामक एक नए निकाय के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया था। हालाँकि, 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 99 वें संवैधानिक संशोधन और एनजेएसी अधिनियम दोनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया।

27. विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है –
(1) महिलाओं की तबादला नीति से
(2) कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से
(3) समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से
(4) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से **[4]**

व्याख्या:-
- विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामला, 1997 कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित था।

28. संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, वह हैं –

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(1) स्वर्ण सिंह समिति (2) शाह आयोग
(3) प्रशासनिक सुधार आयोग (4) संथानम समिति **[1]**

व्याख्या:-

- मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफ़ारिशें करने के लिए 1976 में स्वर्ण सिंह समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी आवश्यकता 1975-1977 में लगाए गए आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी. समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की।

29. भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए –

(1) समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता – अनुच्छेद-42
(2) कृषि और पशुपालन का संगठन – अनुच्छेद-43
(3) ग्राम पंचायतों का संगठन – अनुच्छेद-41
(4) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो – अनुच्छेद-39 **[4]**

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-39(घ) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए।
- 'समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता' का प्रावधान अनुच्छेद - (39A) में है, जबकि अनुच्छेद-42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है।
- 'कृषि और पशुपालन का संगठन' अनुच्छेद-48 के अंतर्गत आता है, जबकि अनुच्छेद-43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन से संबंधित है।
- 'ग्राम पंचायतों का संगठन' भारतीय संविधान के अनुच्छेद-40 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद-41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है।

30. निम्नलिखित में से किसने कहा था, "एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं. भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है?

(1) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (2) जवाहर लाल नेहरू
(3) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (4) महात्मा गांधी **[1]**

व्याख्या:-

- यह कथन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का है।

31. सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

(1) सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना
(2) हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करें
(3) समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों (वर्गों) को सशक्त करने के लिए काम करना
(4) नागरिकों को सशक्त करना **[3]**

व्याख्या:-

- आरटीआई अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है।

2018

32. भारतीय संविधान सभा के सम्बन्ध में निम्नांकित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी।
(ब) यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
(स) यह बहुदलीय संरचना नहीं थी।
(द) यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-

(1) (अ) और (द) (2) केवल (ब)
(3) (ब) और (स) (4) (अ), (ब), (स) और (द) **[1]**

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान सभा से संबंधित तथ्य–
(1) यह सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
(2) इसका निर्माण अनेक दलों के सदस्यों द्वारा किया गया था।
(3) इसका निर्माण वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।
(4) इस सभा का कार्य कई समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता था

33. "भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबन्ध करें", अन्त:स्थापित किया गया–

(1) 15वें संविधान संशोधन द्वारा
(2) 16वें संविधान संशोधन द्वारा
(3) 17वें संविधान संशोधन द्वारा
(4) 18वें संविधान संशोधन द्वारा **[1]**

व्याख्या:-

- 15वाँ संविधान संशोधन, 1963
(1) उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की उम्र निर्धारण के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था।
(2) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश का उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायधीश के रूप में भी नियुक्ति का प्रावधान।
(3) एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण पर न्यायधीशों को होने वाली क्षति के भुगतान हेतु भत्ते का प्रावधान।
(4) उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 2 वर्ष बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई।
(5) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायधीशों के रूप में नियुक्ति का प्रावधान।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(6) उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी रिट दायर करने का अधिकार, यदि इसका कारण उसके न्यायक्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो।

34. मूल अधिकारों से सम्बन्धित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए-
(अ) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(ब) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(स) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
(द) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
सही उत्तर का चयन कीजिए-
(1) (द), (ब), (स), (अ) (2) (अ), (ब), (स), (द)
(3) (द), (अ), (ब), (स) (4) (द), (स), (ब), (अ) **[3]**

व्याख्या:-
- एम. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद (1950 प्रथम मामलें में न्यायालय ने कहा कि, अनु. 21 तहत् प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत् ही किया जा सकता है।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही वापस ले सकती है
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुऐ कहा कि संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है तथा मूल अधिकारों को वापस ले सकती है। बशर्ते संविधान की मूल संरचना ने संशोधन या छेड़छाड़ किये बिना
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि अनु. 368 के अंतर्गत किये गये संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है तथा न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का भाग माना।

35. निम्नांकित में कौन स्वर्णसिंह समिति (1976) के सदस्य रहे हैं?
(अ) ए.आर. अन्तुले (ब) एस.एस. रे
(स) हरिदेव जोशी (द) सी.एम. स्टीफन
सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-
(1) (अ), (ब), (स) और (द)
(2) (अ), (ब) और (स)
(3) (अ), (ब) और (द)
(4) (ब), (स) और (द) **[3]**

व्याख्या:-
- वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों की के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें रखी गयीं।
- इसके प्रमुख सदस्य- ए.आर. अन्तुले, सी. एम. स्टीफन, एस. एस. रे थे।
- 42वें संविधान संशोधन (1976) में भारतीय संविधान के भाग IV-A के अनु. 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- 86 वें संविधान संशोधन (2002) में 11वें मौलिक कर्त्तव्य के रूप में "6-14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना" को जोड़ा गया।

36. भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(1) 240 (1) (क) - अंडमान और निकोबार द्वीप
(2) 240 (1) (ख) - लक्षद्वीप
(3) 240 (1) (ग) - पुदुचेरी
(4) 240 (1) (घ) - दमन और दीव **[3]**

व्याख्या:-
- संविधान के अनु. 240 में राष्ट्रपति को कुछ निश्चित भारतीय संघ क्षेत्रों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये अधिकार संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित निम्न है-
  (1) Art. 240 (क) - अण्डमान और निकोबार द्वीप
  (2) Art. 240 (ख) - लक्षद्वीप
  (3) Art. 240 (ग) - दमन और दीव
  (4) Art. 240 (घ) - दादर और नागर हवेली
  (5) Art. 240 (च) – पुदुचेरी
- **Note -** 26 Jan. 2020 को Art. 240 (ग) तथा 240 (घ) में संशोधन करके दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप केन्द्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित कर दिया गया है।
- 31 Oct. 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य का विघटन कर Art. 240 में दो नये केन्द्रशासित प्रदेशों लद्दाख तथा जम्मू- कश्मीर को सम्मिलित किया गया है।
- वर्तमान में भारतीय राज्य संघ में कुल 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

37. निम्नांकित में से कौनसी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात् विद्यमान है, जिसके कारण आन्तरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है?
(1) 26 अक्टूबर, 1962 (2) 3 दिसम्बर, 1971
(3) 25 जून, 1975 (4) 26 जून, 1975 **[3]**

व्याख्या:-
- 25 जून, 1975 को भारतीय संविधान के अनु. 352 के तहत् तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की।
- प्रसिद्ध समाजवादी ने जयप्रकाश नारायण ने इस आपातकाल को " भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि" कहा।

38. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है-
(1) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
(2) संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में
(3) संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में
(4) एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में **[4]**

व्याख्या:-
- अनु. 87 के तहत वे दो स्थितियाँ राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा-

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(1) प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र में
(2) प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ के प्रथम सत्र में

- राष्ट्रपति अनु. 108 के तहत होने वाले संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

39. लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं?

(1) 19 (3) 21
(2) 20 (4) 22 **[2]**

व्याख्या:-

- संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत वर्णित नियम 377 में वैसे मुद्दे जो सदन की कार्यसूची में शामिल नहीं हो, को विशेष उल्लेखों के जरिए उठाया जा सकता है।
- यह नियम सदस्यों को आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने का अवसर देता है।
- वर्तमान में नियम 377 के तहत् एक दिन में सदस्य 20 मुद्दों को सदन में उठा सकते हैं।
- सन् 1954 में इस प्रक्रियात्मक प्रणाली को संसद में शुरू किया गया था।

40. निम्नांकित में से कौन-सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं?

(अ) प्राक्कलन समिति
(ब) लोक लेखा समिति
(स) लोक उपक्रम समिति
(द) संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए- कूट-

(1) (अ), (स) और (द) (2) (अ), (ब) और (द)
(3) (अ), (ब) और (स) (4) (ब), (स) और (द) **[3]**

व्याख्या:-

- लोक लेखा समिति- 1921 में पहली बार गठन, 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)
- प्राक्कलन समिति- जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में, कुल सदस्य 30 (सभी लोकसभा), कार्यकाल - 1 वर्ष
- लोक उपक्रम समिति- इसके कुल सदस्य 22 (15 लोकसभा और 7 राज्यसभा)

41. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है?

(1) लोकसभा अध्यक्ष
(2) भारत का महान्यायवादी
(3) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(4) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष **[3]**

व्याख्या:-

- अनु. 149 के तहत् CAG को कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया के आभार पर हटा सकता है।

42. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई?

(1) गोरवाला प्रतिवेदन
(2) कृपलानी समिति
(3) सन्थानम समिति
(4) भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग **[3]**

व्याख्या:-

- 1962 में गठित संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए 1964 में केन्द्रीय सर्तकता आयोग (CVC) की स्थापना की गई।
- CVC - संरचना - 1 मुख्य आयुक्त + 2 अन्य आयुक्त कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष
- वर्तमान CVC - संजय कोठारी

43. जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है?

(1) कनाडा (2) संयुक्त राज्य अमेरिका
(3) यूनाइटेड किंगडम (4) ऑस्ट्रेलिया **[2]**

व्याख्या:-

- जनहित याचिका की संकल्पना संयुक्त– राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई।
- भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय पी. एन. भगवती को जाता है।
- एक ऐसी याचिका जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति या संरचना या न्यायालय स्वयं संज्ञान में लेकर पीड़ित व्यक्ति का मुद्दा उठा सके जनहित याचिका कहलाती है।

44. निम्नांकित में से कौन-सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है?

(अ) सूचना की पारदर्शिता
(ब) सूचना का प्रकटन
(स) ससूचित नागरिकता
(द) लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-

(1) केवल (अ)
(2) केवल (अ) और (ब)
(3) केवल (अ), (ब) और (स)
(4) (अ), (ब), (स) और (द) **[4]**

व्याख्या:-

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 13 अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया।
- राज्य का कोई भी नागरिक प्रबंधित नियमों के तहत् किसी भी सरकारी मंत्रालय या विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता व लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता उल्लेखित है।

45. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

सूची-I लेखक		सूची-II पुस्तकें	
A.	अतुल कोहली	I.	डिवाइड एण्ड क्विट
B.	ग्रेनविल ऑस्टिन	II.	द सक्सेस ऑफ इण्डियाज डेमोक्रेसी
C.	पेन्डेरल मून	III.	द रिपब्लिक ऑफ इण्डिया: डेवलपमेंट कॉन्स्टीट्यूशन
D.	एलन ग्लेडहिल	IV.	वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टीट्यूशन : ए हिस्ट्री ऑफ द इण्डियन एक्सपीरियंस

कूट-

	A	B	C	D
(1)	III	IV	I	II
(2)	II	I	III	IV
(3)	II	IV	I	III
(4)	I	II	III	IV

[3]

व्याख्या:-

- अतुल कोहली - द सक्सेस ऑफ दी इंडियाज डेमोक्रेसी -
- ग्रेनविल ऑस्टिन- वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टीट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इण्डियन एक्सपीरियंस
- पेन्डेरल मून- डिवाइड एण्ड क्विट
- एलन ग्लेडहिल - द रिपब्लिक ऑफ इण्डिया: डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एण्ड कॉन्स्टीट्यूशन

46. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबन्धों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिये आता है, तो

(अ) विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है।
(ब) विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है।
(स) ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए–

(1) केवल (अ) (2) केवल (ब) और (स)
(3) केवल (अ) और (स) (4) (अ), (ब), और (स) [4]

व्याख्या-

- भारतीय संविधान में इसके उपबंधों के तहत् यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास अनुसमर्थन हेतु आता है तब- विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है परन्तु विधानसभा उत्त प्रस्तावित संकल्प के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं कर सकती।

2016

47. निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइये–

(1) बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।
(2) मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।
(3) हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था।
(4) गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। [2]

व्याख्या:-

- वर्ष 1969 में, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया जबकि मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया।
- 1960 ई. में बंबई को महाराष्ट्र तथा गुजरात में विभाजित किया गया था।
- 1 नवम्बर, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केन्द्र शासित प्रदेश, जबकि 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- वर्ष 1987 में गोवा को दमन व दीव से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

48. संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया?

(1) 1975 में (2) 1976 में
(3) 1978 में (4) 1979 में [2]

व्याख्या:-

- मूल कर्त्तव्य संविधान के भाग-4 (क) में वर्णित है।
- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गये। इसकी संकल्पना साम्यवादी रूस से ली गयी है।
- 86वें संविधान संशोधन (2002) में 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान कर 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया।

49. केन्द्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है–

(1) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
(2) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
(3) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
(4) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक [3]

व्याख्या:-

- मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नियत हो 5 वर्ष का सेवा काल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते है, उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा एक कैबिनेट मंत्री द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर, 2005 को लागू किया गया। RTI Act 2005 की धारा 3 तथा धारा 4 में क्रमश: केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है।
- वर्तमान में केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है।

50. निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है?

(1) लोक सभा (2) राज्य सभा
(3) विधान परिषद् (4) विधान सभा [3]

व्याख्या:-

- विधान परिषद को कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- विधान परिषद् की स्थापना और समाप्ति – अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान सभा अपने कुल सदस्य के बहुमत से वोट डालने वाले सदस्य के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है।

51. राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेसा [(पंचायत अनुसचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम], 1996 प्रवर्तनीय नहीं है?

(1) असम - मेघालय - तमिलनाडु
(2) राजस्थान - तेलंगाना- महाराष्ट्र
(3) हिमाचल प्रदेश - गुजरात - छत्तीसगढ़
(4) आंध्र प्रदेश - झारखण्ड-ओड़िशा **[1]**

व्याख्या:-

- राजस्थान में पेसा अधिनियम 2 नवम्बर, 2011 को लागू हुआ पेसा अधिनियम भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दर्ज ऐसे क्षेत्रों में लागू होते है जहाँ 50% से अधिक जनजातीय आबादी निवास करती हो।
- इसे पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्युल एरियाज एक्ट, 1996 के तहत् लागू किया गया।
- राज्य– मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, हिमाचल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र में।
- राजस्थान में बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही के आबु रोड़ में लागू है।

52. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोक सभा में केवल एक सीट है?

(1) अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप
(2) गोवा, मेघालय, नागालैंड
(3) चण्डीगढ़, सिक्किम, मिजोरम
(4) मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी **[3]**

व्याख्या:-

- भारत के राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ लोकसभा में केवल एक सीट है- नागालैण्ड, सिक्किम, मिजोरम पुडुचेरी चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव अंडमान एवं निकोबार।
- केवल 2 लोकसभा सीट वाले राज्य - त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर।
- सर्वाधिक - UP (80), महाराष्ट्र (48), बंगाल (42) राजस्थान एवं आन्ध्रप्रदेश में 25-25 सीट।

53. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए–

सूची-I		सूची-II	
A.	**उपाधियों का निषेध**	**I.**	**अनुच्छेद 29**
B.	**धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता**	**II.**	**अनुच्छेद 21 क**
C.	**अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण**	**III.**	**अनुच्छेद 18**
D.	**शिक्षा का अधिकार**	**IV.**	**अनुच्छेद 26**

कूट:

	A	B	C	D
(1)	II	III	IV	I
(2)	III	II	I	IV
(3)	III	IV	I	II
(4)	IV	III	II	I

[3]

व्याख्या:-

- भारत के संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के अन्तर्गत अनु. 18 में उपाधियों का निषेध, स्वतंत्रता के अन्तर्गत अनु. 21 (क) में बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत अनु.26 में धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनु.29 में अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण सम्बन्धी मूल अधिकार वर्णित है।

54. भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है-

(1) न्यायिक प्रक्रिया (2) अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया
(3) विधायी प्रक्रिया (4) कार्यपालिका प्रक्रिया **[2]**

व्याख्या:-

- संविधान के अनु. 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन महाभियोग के सम्बन्ध में आरोप लगाता है।
- यह प्रक्रिया एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है-
  (1) इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते है।
  (2) संघ शासित क्षेत्रों तथा राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते है।

2015

55. संविधान संशोधन करने के विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। इस शब्द से स्थापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है-

(1) तेइसवाँ संशोधन
(2) चौबीसवाँ संशोधन
(3) बयालिसवाँ संशोधन
(4) चवालिसवाँ संशोधन **[2]**

व्याख्या:–

- 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखण्ड (1) तथा (3) के तहत् संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अपनी अनुमति देगा।
- इस प्रकार राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया।

56. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है-

(1) पहले
(2) दूसरे
(3) तीसरे

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(4) चौथे **[3]**

व्याख्या:–

- सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गये हैं।
- मौलिक कर्तव्यों की सूची में तीसरे स्थान पर भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाये रखने के मूल कर्त्तव्य को रखा गया है।

57. संविधान में कौन-सा भाग पंचायत से संबंधित है?

(1) भाग-आठ
(2) भाग -नौ
(3) भाग-नौ-ए
(4) भाग -नौ-बी **[2]**

व्याख्या:–

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (24 अप्रैल, 1993) के द्वारा संविधान में भाग - IX एवं 11वीं अनुसूची (पंचायत) को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया।

58. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए-

A. 44वें संवैधानिक संशोधन, 1978 द्वारा राज्य के सभी नीति निदेशक तत्त्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है

B. मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 (ख) एवं (ग) में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है।

(1) केवल A सही है।
(2) केवल B सही है।
(3) A व B दोनों सही हैं।
(4) न तो A न ही B सही है **[2]**

व्याख्या:–

- 44वें संवैधानिक संशोधन (1978) द्वारा नहीं, बल्कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के सभी नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP) को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया था। इसलिए कथन A पूरी तरह असत्य है।
- मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन के उस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसने सभी नीति निदेशक तत्त्वों को प्राथमिकता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 (ख) एवं (ग) में उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्वों को ही अनुच्छेद 14 और 19 के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता (25वें संशोधन, 1971 के प्रावधान के तहत) प्राप्त रहेगी, जो कि संवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच संतुलन संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा है।

59. सुमेलित कीजिए-

	संवैधानिक संशोधन का प्रावधान		संवैधानिक संशोधन का क्रमांक
A.	अनु. 19 (1) (ग) के अंतर्गत सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार	I.	81वाँ संशोधन, 2000
B.	रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण	II.	91वाँ संशोधन, 2004
C.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण	III.	97वाँ संशोधन, 2012
D.	मंत्रिपरिषद् के आकार को परिमिति करना।	IV.	99 वाँ संशोधन, 2015

कूट :

	A	B	C	D
(1)	I	IV	II	III
(2)	III	I	IV	II
(3)	II	III	I	IV
(4)	III	II	IV	I

[2]

व्याख्या:–

- अनु. 19 (1) (ग) के अंतर्गत सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार-97वाँ संशोधन, 2012
- रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण-81वाँ संशोधन, 2000
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण-99 वाँ संशोधन, 2015
- मंत्रिपरिषद् के आकार को परिमिति करना-91वाँ संशोधन, 2004

60. सुमेलित कीजिए-

	संवैधानिक प्रावधान		स्रोत
A.	मौलिक अधिकार	I.	ब्रिटिश संविधान
B.	राज्य के नीति निदेशक तत्त्व	II.	कनाडा का संविधान
C.	मंत्रिमंडलीय सरकार	III.	आईरिश संविधान
D.	केंद्र राज्य सम्बन्ध	IV.	अमेरिकी अधिकार पत्र

कूट :

	A	B	C	D
(A)	IV	II	III	I
(B)	IV	I	III	II
(C)	IV	III	I	II
(D)	IV	III	II	I

[3]

व्याख्या:-

संवैधानिक प्रावधान	स्रोत
एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्री मण्डलीय शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, द्वि-सदनीय व्यवस्था	इंग्लैण्ड

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरवलोकन, संघात्मक शासन के प्रावधान, वित्तीय आपातकाल, न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया	अमेरिका
नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मण्डल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन	आयरलैण्ड

61. कथन A : भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहु-आयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था
कारण B : विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है

(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की पुष्टि करता है।
(2) A और R दोनों सही हैं और R, A की पुष्टि नहीं करता है।
(3) A सही है और R गलत है।
(4) A गलत है और R सही है। **[1]**

व्याख्या:-
- भारत ने संघीय (संघात्मक) ढांचा इसलिए चुना ताकि देश की विशाल विविधताओं (भाषा, संस्कृति) को एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके।
- भारत में विविधताओं को दबाया नहीं गया, बल्कि उन्हें स्वीकार किया गया। इसी तालमेल (समंजन) के कारण आज भारतीय राष्ट्रीयता कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हुई है।

62. सुमेलित कीजिए–

	वाद		विषय
A.	**ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य**	**I.**	**शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता**
B.	**रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य**	**II.**	**संविधान संशोधन की संसद की शक्ति**
C.	**शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ**	**III.**	**निवारक अवरोध की प्रक्रिया**
D.	**चम्पकदोराइजन बनाम मद्रास राज्य**	**IV.**	**स्वतंत्र भाषण पर रोक**

कूट :

	A	B	C	D
(1)	III	IV	I	II
(2)	II	IV	I	III
(3)	IV	III	II	I
(4)	I	II	III	IV

[*]

व्याख्या:-
- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

63. सुमेलित कीजिए-

	सूची-I घटना		सूची-II समय
A.	**भारत शासन अधिनियम**	**I.**	**1935**
B.	**क्रिप्स प्रस्ताव**	**II.**	**1940**
C.	**अगस्त प्रस्ताव**	**III.**	**1945**
D.	**वेवेल योजना**	**IV.**	**1942**

कूट :

	A	B	C	D
(1)	I	IV	II	III
(2)	I	IV	III	II
(3)	I	II	III	IV
(4)	IV	III	II	I

[1]

व्याख्या:-

भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ एवं समय	
घटना	**समय**
बंगाल विभाजन	16 Oct, 1905
सूरत विभाजन (कांग्रेस का अधिवेशन)	1907
अहमदाबाद मिल हड़ताल	1918
खेड़ा सत्याग्रह	1918
खिलाफत आंदोलन	1918
क्रिप्स मिशन	March 1942
देसाई - लियाकत पैक्ट	Jan. 1945
वेवेल योजना	June 1945
कैबिनेट मिशन	24 March 1946

64. सुमेलित कीजिए-

	सूची-I पुस्तक		सूची-II लेखक
A.	**गाँधीयन कांस्टीट्यूशन फॉर इंडिया**	**I.**	**डी. मेकेन्जी ब्राउन**
B.	**द रिपब्लिक ऑफ इंडिया**	**II.**	**श्रीमन नारायण**
C.	**द व्हाइट अम्ब्रेला**	**III.**	**ए. ग्लेडहिल**
D.	**द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिन्स इंडिपेंडेंस**	**IV.**	**पॉल आर. ब्रास**

कूट :

	A	B	C	D
(1)	II	I	IV	III
(2)	II	III	I	IV
(3)	I	II	III	IV
(4)	II	IV	I	III

[*]

व्याख्या:-
- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

65. निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया?

(1) 54वाँ (2) 55वाँ
(3) 52वाँ (4) 53वाँ **[4]**

व्याख्या:-
- 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

66. निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए–

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

कथन A : सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए।
कारण B : जिन राजनीतिक दलों ने केन्द्र में सरकार बनायी उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की पुष्टि नहीं करता है।
(2) A और R दोनों सही हैं और R, A की पुष्टि करता है।
(3) A सही है और R गलत है।
(4) A गलत है और R सही है। **[2]**

व्याख्या:-
- सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में केन्द्र राज्य सम्बंधो के लिए की गई।
- सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केन्द्र में सरकार बनायी, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

67. निम्नलिखित में से कौन जून, 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किये गये?
(1) श्री नन्दन नीलेकणी
(2) श्री अशोक देसाई
(3) श्री राम सेवक शर्मा
(4) श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया **[3]**

व्याख्या:-
- वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार) के महानिदेशक अमित अग्रवाल है। जून, 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रथम महानिदेशक श्री राम सेवक शर्मा को नियुक्त किया गया था।

68. सुमेलित कीजिए-

सूची-I मानवाधिकार प्रलेख		सूची-II वर्ष	
A.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम	I.	1990
B.	बाल मज़दूर (निषेध एवं नियामक अधिनियम)	II.	1995
C.	नि:शक्तजन (समान अधिकारिता, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) - अधिनियम	III.	1986
D.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	IV.	1993

कूट :

	A	B	C	D
(1)	IV	III	II	I
(2)	III	I	II	IV
(3)	III	I	IV	II
(4)	II	I	III	IV

[*]

व्याख्या:-
- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213